भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3030
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

तेलंगाना में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

3030. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तेलंगाना में पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों द्वारा राज्य में लाभ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को आमतौर से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के रूप में जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी संचालित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने हक का खाद्यान्न उठाने का अधिकार दिया गया है। घर पर मौजूद परिवार भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा उठा सकता है। ओएनओआरसी पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए एक सार्वभौमिक सुविधा है और तेलंगाना के लिए कोई अलग से धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ): ओएनओआरसी सुविधा देश भर में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तेलंगाना सहित) में सक्षम है, जो लगभग 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को कवर करती है। ओएनओआरसी सुविधा की स्थापना के बाद से इसके तहत 168.5 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन (तेलंगाना में 12.62 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन सहित) दर्ज किए गए हैं, जिसमें अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं।

*****